



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 1994/आषाढ़ 24, 1916

No. 302]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1994/ASADHA 24, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1994

सा.कां.नि. 587(अ):—ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-0(3) की उपधारा (3) में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अधिम निर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तों, वेतन और भत्तों को समझित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और उनका प्रभावी होना :—

(1) इन नियमों का अधिम निर्णय प्राधिकरण नियमावली, 1994(अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते) कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जहाँ तक कि भिन्न संदर्भ अपेक्षित न हों :—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य ग्रायकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) है ;

(ख) "प्राधिकरण" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 245-0 के अधीन संस्थापित अधिम निर्णय प्राधिकरण है;

(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य प्राधिकरण का अध्यक्ष है;

(घ) "सदस्य" से तात्पर्य प्राधिकरण का सदस्य है।

3. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते आदि :—

(1) अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन के समान दर का मासिक वेतन पाने के हकदार होंगे।

वर्षों कि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान पेंशन और किसी अन्य रूप में पेंशन के समकक्ष प्राप्त होने वाला वेतन सेवा निवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा लिये गये वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश के समान स्वीकृत भत्ते और अन्य सुविधायें प्राप्त करने के हकदार होंगे।

4 सदस्यों का वेतन और भत्ते आदि :—सदस्य को 7300-200-7500-250-8000/- रु. प्रति माह के वेतनमान में वेतन प्राप्त होगा ;

बशर्ते कि पेंशन और ग्रेजुटी के समकक्ष पेंशन की राशि द्वारा कर्मचारी का अंशदायी फण्ड में अंशदान अथवा किसी अन्य रूप में सेवा निवृत्ति लाभ यदि कोई है और उनके द्वारा निकाला गया अथवा निकाला जाना है उल्लिखित वेतन में से काट लिया जायेगा।

5 महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपत्ति भत्ता :—सदस्य, केन्द्र सरकार में समकक्ष वेतन पाने वाले ग्रुप "क" के अधिकारी को स्वीकृत दर पर मिलने वाला महंगाई भत्ता और नगर भत्ता प्राप्त करेगा।

6 छुट्टी :—अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के एक अधिकारी को मिलने वाली ऐसी स्वीकृत छुट्टियों का हकदार होगा।

बशर्ते कि सदस्य द्वारा सरकार में सेवा निवृत्ति पर नकद भुनाई जाने वाली छुट्टी और प्राधिकरण में सेवा अवधि की समाप्ति पर नकद भुनाई जाने वाली कुल छुट्टी 240 दिन तक सीमित रहेगी।

7 छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी :—सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिये अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी होंगे।

8 कार्यालय की शर्तें :—अध्यक्ष अथवा सदस्य कार्यभार सम्भालने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा शर्त कार्यालय को सम्भालेंगे परन्तु वे अगले तीन वर्षों की और अवधि के लिये पुर्ननियुक्ति के पात्र होंगे।

बशर्ते कि कोई अध्यक्ष अथवा सदस्य उनके अधिवाधिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् कार्यालय नहीं सम्भाल सकेगा :—

(क) किसी अध्यक्ष के 70 वर्ष की आयु के मामले में, और

(ख) किसी सदस्य के 62 वर्ष की आयु के मामले में,

2. सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सदस्य के रूप में कार्यभार सम्भालने से पूर्व सरकारी सेवा में सेवा-निवृत्ति लेनी होगी।

9. अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान :—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति पर लागू होने वाली शर्तों के तहत अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत) 1962 के अनुरूप अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख में अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के हकदार होंगे।

10. सेवा की अन्य शर्तें :—(1) अध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिये इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) अधिनियम, 1959 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों से नियंत्रित होंगी। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीशों को समय-समय पर मिलने वाले भत्तों, परिपक्वियों, विशेषाधिकार, सुविधाओं और सहूलियतों को पाने के हकदार होंगे।

(2) जिन विषयों के संबंध में इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है वहां सदस्यों की सेवा शर्तें, भारत सरकार के समकक्ष अधिकारियों पर लागू होने वाली सेवा शर्तों के समान होंगी।

11. अर्वाश्रित उपबंध :—अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किये गये हैं, उसके निर्णय के लिये प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार की राय ली जायेगी और केन्द्र सरकार का निर्णय अध्यक्ष या अन्य सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

12. ढील देने की शक्ति :—केन्द्र सरकार को, किसी भी संवर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में ढील देने की शक्ति होगी।

[स. 4/94/फा सं. 23/1/93-प्रशा.-Iग]

ए.के. सिन्हा, डैरक अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1994

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 245-0(3) of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the salaries and allowances, terms and conditions of service of Chairman and Member of the Authority for Advance Rulings, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Authority for Advance Rulings (salaries and allowances, terms and conditions of service of Chairman and Members) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) 'Act' means the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (b) 'Authority' means the Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act;
- (c) 'Chairman' means Chairman of the Authority;
- (d) 'Member' means a Member of the Authority.

3. Salary, allowances etc. of the Chairman.—

(1) The Chairman shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a Judge of the Supreme Court :

Provided that such salary, which together with the pension and pension equivalent of any other form of retirement benefit shall not exceed the last pay drawn by him before retirement as a Judge of the Supreme Court.

(2) The Chairman shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court.

4. Pay and allowances etc. of Members.—A Member shall receive pay in the scale of Rs. 7300-200-7500-250-8000 per month :

Provided that the aforementioned pay shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of gratuity, employer's contribution to the contributory fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

5. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.—A Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

6. Leave.—A person appointed as Chairman or Member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Central Government under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 :

Provided that the encashment of leave taken on retirement from Government by a Member and the leave to be encashed at the end of the tenure in the Authority shall be restricted to a total of 240 days.

7. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to a Member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

8. Terms of office.—(1) The Chairman or Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office, but shall be eligible for re-appointment for another terms of three years :

Provided that no Chairman or Member shall hold office as such after he has attained :—

- (a) in the case of any Chairman, the age of seventy years, and
- (b) in the case of any Member, the age of sixty two years.

(2) A person, when appointed as a Member, shall seek retirement from Government service before he enters upon his office as a Member.

9. Contribution to Contributory Provident Fund.—The Chairman and Members shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund from the date of their appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.

10. Other Conditions of Service.—(1) The conditions of service of Chairman for which no provision is made in these rules shall be governed by the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Act, 1959 and the Rules framed thereunder. The Chairman shall also be entitled to all the allowances, perquisites, privileges, amenities and facilities as are admissible to sitting Judges of the Supreme Court from time to time.

(2) The conditions of service of Members in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as may be applicable to other equivalent officers of the Government of India.

11. Residuary provisions.—Matters relating to the conditions of service of the Chairman or other Members with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairman or the other Members.

12. Power to relax.—The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[F. No. 23/1/93-Ad-IC]
A. K. SINHA, Desk Officer

